

## उच्चति वर्गीकरण परीक्षण

### प्रलिस के लयि:

उच्चति वर्गीकरण, अनुच्छेद 14, [वशिष नयायालय](#), [सत्र नयायालय](#), [उच्च नयायालय](#), [सरवोच्च नयायालय](#) ।

### मेन्स के लयि:

उच्चति वर्गीकरण सदिधांत का वकिस एवं सामाजकि नयाय प्रदान करने में इसका महत्त्व ।

[सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यो?

भारतीय संवधान के अनुच्छेद 14 के तहत अनवर अली सरकार मामला, 1952 द्वारा "उच्चति वर्गीकरण" परीक्षण का आधार तैयार हुआ ।

- यह परीक्षण अब कानूनों की संवैधानकिता के मूल्यांकन के लयि एक मानक बन गया है ।

## उच्चति वर्गीकरण परीक्षण क्या है?

- **परचिय:** यह भारतीय संवधान के अनुच्छेद 14 के तहत एक वधिकि सदिधांत है जो स्पष्ट मतभेदों के आधार पर व्यक्तियों या संस्थाओं के समूहीकरण की अनुमता देकर नषिपक्ष व्यवहार सुनश्चिति करने पर केंद्रति है ।
  - मनमाने भेदभाव को रोकने के साथ इसके तहत स्वीकार कया गया है कसभी मामले एक जैसे नहीं होते हैं ।
- **वशिषताएँ:**
  - वर्गीकरण स्पष्ट एवं उच्चति अंतर पर आधारति होना चाहयि ।
  - यह अंतर तार्ककि रूप से कानून के उद्देश्य से जुडा होना चाहयि ।
  - वर्गीकरण में अधिकारों का उल्लंघन कयि बना सामाजकि या नीतगित आवश्यकताओं को धयान में रखा जाना चाहयि ।
  - बडे समूहों को मनमाने ढंग से अलग-अलग व्यवहार के लयि नहीं चुना जा सकता (कोई वर्ग वधिान नहीं) है । इसके तहत उपचार में यादृच्छकि नहीं, बल्कि उच्चति अंतर सुनश्चिति करना चाहयि ।
- **महत्त्व:**
  - **वशिषिट वनियिमां का समर्थन:** यह अलग-अलग सामाजकि स्थतियिों के लयि अनुरूप वधियिों की अनुमता देता है, यह सुनश्चिति करता है कसमान व्यवहार से अनुचतिता न हो ।
    - यह अतार्ककि परिणामों को रोकने के लयि वधियिों की व्याख्या करने में वधिनिरिमाताओं और नयायाधीशों का मार्गदर्शन करता है ।
  - **वैधता परीक्षण:** यह वधियिों की वैधता का आकलन करता है, तर्कसंगतता सुनश्चिति करता है और वधिकि चुनौतियिों को कम करता है ।
  - **नयायकि समीक्षा के लयि मानक:** यह नयायालयों के लयि तर्कहीन या अवविकपूरण प्रशासनकि कार्यों की समीक्षा करने तथा उन्हें नरिसत करने के लयि एक मानक प्रदान करता है, जसिसे वधियी जवाबदेही सुनश्चिति होती है ।
- **सीमाएँ:**
  - **अनुचति वभिदीकरण का जोखमि:** यदइसे उच्चति रूप से लागू नहीं कया गया तो इससे अनयायपूरण भेदभाव को बढ़ावा मलिया तथा मौलकि अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है ।
  - **व्यक्तपिरकता:** वर्गीकरण कारक (जैसे, आयु, लगी, शारीरकि शक्ति) व्यक्तपिरक हो सकते हैं, जसिसे सदिधांत की असंगत नयायकि व्याख्या हो सकती है ।

## अनवर अली सरकार केस, 1952 क्या है?

- **पृष्ठभूमि:** वर्ष 1950 में, अनवर अली सरकार को अलीपुर [सत्र नयायालय](#) द्वारा पश्चमि बंगाल वशिष नयायालय अधनियम, 1950 के तहत

दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय (1952): सर्वोच्च न्यायालय ने वशिष न्यायालयों को मामलों को मनमाने ढंग से संदर्भित करने की अनुमति देने वाली वधि को यह कहते हुए अमान्य कर दिया कि वर्गीकरण में वैध उद्देश्य के साथ तार्किक संबंध का अभाव है।
  - इस नरिणय ने “उचित वर्गीकरण” परीक्षण की स्थापना की, जो कुछ शर्तों के तहत अनुच्छेद 14 के तहत समता के अपवाद की अनुमति देता है।

## अनुच्छेद 14 (वधि के समक्ष समता)

- परचिय: किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या वदिशी, भारत में वधि के समक्ष समता या वधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता।
  - वधि के समक्ष समता किसी भी वशिष वशिषाधिकार को सुनिश्चित नहीं करती है, सभी पर समान वधियाँ लागू होती हैं। वधियों का समान संरक्षण समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की गारंटी देता है।
- उचित वर्गीकरण: अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वर्ग वधि का निषिध किया गया है, लेकिन बोधगम्य भिन्नताओं (पहचान योग्य भेद) के आधार पर उचित वर्गीकरण किये जाने का प्रावधान किया गया है।

## युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धांत पर न्यायिक रुख

- [1972] [1972] [1972], 2004: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दो प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किये गए:
  - सुबोध वधि: वर्गीकरण किसी समूह को अलग करने के लिये स्पष्ट और वशिषित कारणों पर आधारित होना चाहिये।
  - तर्कसंगत संबंध: वर्गीकरण का वधि के उद्देश्य से तार्किक संबंध होना चाहिये।
- [1972] [1972] [1972] [1972] [1972], 1958: कोई कानून संवैधानिक हो सकता है यदि वह वशिष दशाओं के कारण किसी वशिषित व्यक्ति पर लागू होता है, तथा उन्हें एक वर्ग के रूप में मानता है।
  - इसमें संवैधानिकता की धारणा है, तथा यह सिद्ध करने का दायित्व आक्षेप कर रहे व्यक्तियों पर है कि यह संवैधानिक मानकों का उल्लंघन है।

## निषिध

[1972] [1972] [1972] [1972], 1952 [1972] अनुच्छेद 14 के तहत "युक्तियुक्त वर्गीकरण" परीक्षण की नींव स्थापित हुई, जिससे निषिधता और समानता सुनिश्चित हुई। यह ऐसे कानूनों को संक्षम बनाता है जिनमें अलग-अलग समूहों के लिये अलग-अलग प्रावधान किये गए हों लेकिन तार्किक औचित्य की आवश्यकता होती है, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हुए मनमाने भेदभाव को रोका जा सकता है।

दृष्टि भेन्स प्रश्न:

प्रश्न. न्यायिक दृष्टिकोण के साथ युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिये।

**UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न**

[1972] [1972] [1972]:

प्रश्न. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समता के अधिकार की धारणा की वशिषित वशिषताओं का वशिलेण कीजिये। (2021)

प्रश्न. 'आधारिक संरचना' के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारत एक उन्नतशील लोकतंत्र के रूप में विकसित हो, एक उच्चतः अग्रलक्षी (प्रोएक्टिव) भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिये हाल के समय में 'न्यायिक सक्रियतावाद' द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (2014)